2024

1. वर्ष 2021-22 में, देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान (प्रतिशत में) था:

(1) 34.69 (2) 46.30
(3) 87.69 (4) 38.98
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- वर्ष 2021-22 में, देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान (प्रतिशत में) 38.98% था। यह आँकड़ा राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Review) और कृषि सांख्यिकी (Agricultural Statistics) विभाग के वर्ष 2021-22 के अग्रिम/संशोधित अनुमानों पर आधारित है।
- राजस्थान देश में बाजरा (Pearl Millet) का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बाजरा, यहाँ की शुष्क और अर्द्ध-शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त होने के कारण, राज्य की खरीफ फसलों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

2. मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है -

(1) बोरानाडा, जोधपुर (अविभाजित)
(2) गणेश्वर विस्तार, सीकर
(3) माल की तूस, उदयपुर
(4) नैनवा, बूँदी
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरानाडा, जोधपुर (अविभाजित) में अवस्थित है। इसे RIICO प्राधिकरण के अंतर्गत बोरानाडा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह पार्क भारत सरकार की 'चिकित्सा उपकरण पार्क को बढ़ावा देने की योजना' (Scheme for Promotion of Medical Device Parks) के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देना और उन्हें एक ही स्थान पर बुनियादी ढाँचा (Infrastructure) प्रदान करना है।

3. राजस्थान के राज निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(1) पोर्टल निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों और नीतिगत पहलों और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है।
(2) राज निवेश पोर्टल मंजूरी/अनुमोदन के लिए वन-स्टॉप सूचना/पंजीकरण/अनुमोदन /ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य करके एकल बिंदु (ऑनलाइन) इंटरफेस और समयबद्ध निकासी प्रणाली प्रदान करता है।
(3) यह बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन/मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक "वन स्टॉप शॉप" (ओ एस एस) सुविधा है।
(4) वन स्टॉप शॉप के नियम 26.11.2020 को अधिसूचित किए गए हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- राज निवेश पोर्टल (Raj Nivesh Portal) और One Stop Shop (OSS) सुविधा का उद्देश्य राज्य में निवेश को आसान बनाना है, लेकिन उनकी प्रशासनिक संरचना भिन्न है।
- वन स्टॉप शॉप (OSS) सुविधा सीधे उद्योग और वाणिज्य विभाग (Department of Industries and Commerce) के अधीन कार्य करती है, न कि सीधे मुख्यमंत्री के अधीन। इसका प्रबंधन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) द्वारा किया जाता है।
- OSS सुविधा के तहत, एक निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) होता है जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है और एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (BOI) होता है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन OSS सुविधा स्वयं BIP के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

4. राजस्थान के राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में निम्न कथनों पर विचार करें :

A. वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76 प्रतिशत रहा है।
B. यह एफआरबीएम अधिनियम, 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है।
C. वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था।
सही विकल्प को चुनिए :

(1) A, B व C सभी सही हैं। (2) A व C दोनों सही हैं।
(3) A व B दोनों सही हैं। (4) B व C दोनों सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76 प्रतिशत रहा है। यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है। वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था।

5. राजस्थान खनिज नीति - 2024 के लक्ष्यों के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिये :

A. वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना।
B. राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2029-30 तक 5 प्रतिशत और 2046-47 तक 8 प्रतिशत तक करना।
C. खनन के अन्तर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

(1) A, B और C (2) केवल A और B
(3) केवल B और C (4) केवल A और C
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

व्याख्या:-

- राजस्थान खनिज नीति-2024 (Rajasthan Mineral Policy - 2024), जिसे मार्च 2024 में जारी किया गया था, के मुख्य लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–
  - वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना।
  - राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2029-30 तक 5 प्रतिशत और 2046-47 तक 8 प्रतिशत तक करना।
  - खनन के अन्तर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना।

6. राजस्थान के सकल स्थायी पूँजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुये क्रम में सही क्रम है -

(1) विनिर्माण, कृषि, खनन, निर्माण
(2) विनिर्माण, खनन, कृषि, निर्माण
(3) निर्माण, कृषि, विनिर्माण, खनन
(4) निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- राजस्थान के सकल स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation - GFCF) में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम है: निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन।

7. भारत में राज्यों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है -

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) द्वारा
(2) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा
(3) उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग द्वारा
(4) निवेश संवर्द्धन ब्यूरो द्वारा
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- भारत में राज्यों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT) द्वारा जारी की जाती है।
- यह रैंकिंग राज्यों के बीच व्यावसायिक सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan - BRAP) के कार्यान्वयन के आधार पर दी जाती है, जिसका उद्देश्य राज्यों में निवेश को आकर्षित करना और व्यवसाय करने को आसान बनाना है।

8. मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् (CMRETAC) के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है?

(1) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका)
(2) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)
(3) राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन (RITI)
(4) राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-कैट)
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद् (CMRETAC) के स्थान पर राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन (RITI) का गठन किया गया है। RITI का उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास, नवाचार और सुधार को बढ़ावा देना है। यह परिषद पहले के CMRETAC के कार्यों को आगे बढ़ाती है और नीतिगत सुझाव प्रदान करती है।

9. निम्नलिखित में से कौन-सा पार्क/ज़ोन RIICO द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है?

(1) एग्रो फूड पार्क - उदयपुर
(2) मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क - बोरानाडा, जोधपुर
(3) इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी - जमवा रामगढ़, पार्क जयपुर
(4) स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज़ जोन - खुशखेड़ा, भिवाड़ी
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

- एग्रो फूड पार्क RIICO द्वारा उदयपुर में विकसित नहीं किया गया है।
- RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) ने राजस्थान में निम्नलिखित चार स्थानों पर एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं– बोरानाडा (जोधपुर), कोटा (रणपुर), अलवर और श्रीगंगानगर।
- RIICO द्वारा निम्नलिखित पार्क/ज़ोन विकसित किए गए हैं–
  - **मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क -** बोरानाडा, जोधपुर: यह राजस्थान का पहला मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, जिसे RIICO द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  - **इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क -** जमवा रामगढ़, जयपुर: यह पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए थोलाई (जमवारामगढ़), जयपुर में विकसित किया गया है।
  - **स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज़ जोन-** खुशखेड़ा, भिवाड़ी: यह राजस्थान का पहला खिलौना और खेल सामान औद्योगिक क्षेत्र है, जिसे खुशखेड़ा, भिवाड़ी (अलवर) के पास विकसित किया गया है।

10. राजस्थान सरकार ने एम-सैण्ड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है। यह प्रभावी रहेगी -

(1) 30 जून, 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक
(2) 31 मार्च, 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक
(3) 31 मार्च, 2030 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक
(4) 31 मार्च, 2032 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-

- राजस्थान सरकार ने एम-सैण्ड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है और यह नीति 31 मार्च, 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक प्रभावी रहेगी। यह नीति निर्माण कार्यों में प्राकृतिक रेत के स्थान पर एम-सैण्ड (निर्मित रेत) के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, ताकि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। नीति के तहत एम-सैण्ड उद्योग को प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य सुविधाएँ दी जाएगी ताकि इसे विस्तार पूर्वक अपनाया जा सके। नीति के कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए यह एक स्पष्ट समय सीमा प्रदान करती है।

11. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गये कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिये :

सूची-I वर्ष 2023-24 में रीको द्वारा विकसित किये गये नये औद्योगिक क्षेत्र		**सूची-II स्थान**	
A.	नाडोल	I.	उदयपुर
B.	धर्मपुरा	II.	झालावाड़
C.	उमरिया	III.	बाड़मेर
D.	माल की तूस	IV.	पाली

कूट :

(1) A-III B-I C-IV D-II
(2) A-IV B-II C-III D-I
(3) A-IV B-III C-II D-I
(4) A-II B-IV C-I D-III
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- नाडोल का स्थान पाली है।
- धर्मपुरा का स्थान बाड़मेर है।
- उमरिया का स्थान झालावाड़ है।
- माल की तूस का स्थान उदयपुर है।

12. पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?
(i) इस योजना के तहत् हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।
(ii) रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान
(iii) योजना पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति तथा अनुदान की शत प्रतिशत ऑनलाइन व्यवस्था
(iv) प्रत्येक आवेदक को 4 प्रतिशत बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान

(1) (i), (iii) और (iv) (2) (i) और (iv)
(3) (i) , (ii) और (iii) (4) (i) और (iii)
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- **पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ प्रमुख कथन निम्नलिखित हैं–**

i. इस योजना के तहत् हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए एक करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किये जाएँगे।
ii. योजना के तहत अनुदान (सब्सिडी) क्षमता-आधारित है, जो कुल लागत का 40% तक हो सकती है (जैसे 2 किलोवाट तक की क्षमता के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट, और 3 किलोवॉट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए ₹18,000 प्रति किलोवॉट)। यह सीधा 30% अनुदान नहीं है।
iii. योजना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण से लेकर अनुदान वितरण तक की पूरी प्रक्रिया एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है।
iv. योजना के तहत, आवेदकों को रियायती दर पर संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन ब्याज दर लगभग 7% के आस-पास है, न कि 4%।

13. "राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण-III)" का मुख्य उद्देश्य है –

(1) नई सड़कों का निर्माण।
(2) शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
(3) शहरी क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा में सुधार।
(4) जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण-III) (Rajasthan Urban Sector Development Program - Phase III) का मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करना है।
- **मुख्य उद्देश्य-** यह कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक (ADB) की सहायता से संचालित है और इसका फोकस निम्नलिखित पर है–

↳ **जल आपूर्ति (Water Supply):** शहरी क्षेत्रों में 24x7 जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और जल वितरण प्रणालियों की दक्षता में सुधार करना।

↳ **स्वच्छता और सीवरेज (Sanitation and Sewerage):** आधुनिक सीवरेज प्रणालियों, सीवेज उपचार संयंत्रों (STPs), और जल निकासी प्रणालियों का विकास करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना।

↳ यह कार्यक्रम सीधे तौर पर आधारभूत शहरी नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

14. राजस्थान में आस्था योजना के लिये निम्न में से कौन पात्र हैं?

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(1) वे परिवार जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो।
(2) विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्ति
(3) विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो
(4) बी.पी.एल. कार्ड धारक
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-

राजस्थान में आस्था योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:

- वे परिवार जिनमें दो या उससे अधिक सदस्य 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के हों।
- परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पात्र परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाता है, जिससे उन्हें बीपीएल के समान विभिन्न लाभ मिलते हैं।

15. राजस्थान की मुख्यमन्त्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है
(1) गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं का सशक्तीकरण
(2) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सशक्तीकरण
(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों का सशक्तिकरण
(4) स्ट्रीट वेन्डर्स का सशक्तीकरण
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- राजस्थान की मुख्यमन्त्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेन्डर्स का सशक्तीकरण है।
- यह योजना केंद्र सरकार की PM स्वनिधि योजना के अनुरूप है, जो विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वालों) को अपना काम फिर से शुरू करने और उसे बढ़ाने के लिए कार्यशील पूँजी ऋण (Working Capital Loan) प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

16. संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन-सा सतत विकास लक्ष्य (SDG) विशेष रूप से "स्थलीय जीवन" (Life on Land) पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है?
(1) SDG-16
(2) SDG-13
(3) SDG-14
(4) SDG-15
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से SDG - 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही वनों का प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से निपटना, भूमि क्षरण और जैव विविधता की हानि को रोकना शामिल है।

17. राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना (फेज-2) के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए।
(1) इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है।
(2) इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा सहायता प्रदान की गई।
(3) इसमें 18 जिले एवं 8 वन्यजीव अभयारण्य सम्मिलित हैं।
(4) इस परियोजना में अभेदा एवं माचिया जैविक पार्क विकसित किए गए हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-

- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना:–
- सहायता– जापान इन्टरनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी (JICA)

फेज-1

- इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2003 में हुआ जो राजस्थान के 18 जिलों में जून, 2010 तक संचालित थी।

फेज-2

- परियोजना अवधि– 8 वर्ष (2011-12 से 2018-19 तक)
- यह परियोजना मूलत- 2011-12 से 2018-19 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई थी लेकिन इसमें 5 वर्ष की अभिवृद्धि वर्ष 2019-20 से 2023-2024 की गई है।
- परियोजना क्षेत्र– राजस्थान राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले एवं 5 गैर मरुस्थलीय जिले तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास 2 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में परियोजना के अन्तर्गत 650 गाँवों में कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त विभाग के माध्यम से निम्न कार्य भी कराये जाएँगे–
  1. गोडावण संरक्षण कार्य
  2. चौसिंगा संरक्षण कार्य
  3. माचिया बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण
  4. सज्जनगढ़ एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्कों का विकास
- परियोजना का उद्देश्य– साझा वन प्रबन्धन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।'
- इस परियोजना में जल संरक्षण को सम्मिलित किया गया है।

18. कॉलम-I (उत्कृष्टता केन्द्र का स्थान) को कॉलम-II (उद्यानिकी फसल) से सुमेलित कर नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए :

कॉलम-I		कॉलम-II	
A.	बस्सी	I.	आम
B.	सगरा भोजका	II.	सीताफल
C.	देवड़ावास	III.	अनार
D.	खेमरी	IV.	अमरूद

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

		V.	खजूर

कूट :
(1) A-IV B-III C-V D-I
(2) A-III B-I C-II D-IV
(3) A-I B-II C-III D-IV
(4) A-III B-V C-IV D-I **[4]**

व्याख्या:-
- **बस्सी (जयपुर):** यहाँ अनार (Pomegranate) का उत्कृष्टता केंद्र है।
- **सगरा भोजका (जैसलमेर):** यह खजूर (Date Palm) के लिए प्रसिद्ध है।
- **देवड़ावास (टोंक):** यहाँ अमरूद (Guava) का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
- **खेमरी (धौलपुर):** यह आम (Mango) के उत्कृष्टता केंद्र के लिए जाना जाता है।

2023

19. चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था-
(1) श्री गंगानगर में (2) भोपालसागर में
(3) केशोरायपाटन में (4) उदयपुर में
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-
- श्रीगंगानगर में 'द गंगानगर शुगर मिल्स' की स्थापना वर्ष 1935 में की गयी थी तथा इसमें चीनी बनाने का कार्य वर्ष 1946 में प्रारम्भ हुआ। यहाँ वर्ष 1968 में चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए एक योजना आरम्भ की गई थी लेकिन इस योजना को अब बंद कर दिया गया है।

20. कालीसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है-
(1) बाराँ (2) झालावाड़
(3) डूँगरपुर (4) बाँसवाड़ा
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-
- कालीसिंध सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ जिले के उण्डेल ग्राम में 3 सितम्बर, 2008 को प्रारम्भ की गई। यह कालीसिंध नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का प्रथम पॉवर प्लांट है, जहाँ सीधे सुपर क्रिटिकल इकाई स्थापित की गई है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 6002×1200 MW है।

21. निम्नांकित में से कौन-सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वॉटर सिवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है।
(1) राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
(2) राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।
(3) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड।
(4) राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट।
(5) अनुत्तरित प्रश्न
[3]

व्याख्या:-
- 19 नवम्बर, 2015 को राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) की स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) है।
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 1970 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है। यह राज्य में हाउसिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।

22. निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है- "कोई भूखा न सोये " ?
(1) बालगोपाल योजना
(2) इंदिरा गाँधी रोजगार गारंटी योजना
(3) अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
(4) इंदिरा रसोई योजना
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[4]**

व्याख्या:-
- 2015 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी, जिसका 20 अगस्त, 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाम बदलकर इन्दिरा रसोई योजना कर दिया था। अशोक गहलोत की सरकार में इस योजना का नारा "कोई भूखा न सोये" था।
- 6 जनवरी, 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने इन्दिरा रसोई योजना का नाम बदलकर फिर से अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपये रहेगी। इसमें सरकारी अनुदान 22 रुपये रहेगा। लाभार्थी का अंशदान पहले की तरह 8 रुपये प्रति थाली ही रहेगा।

23. राजस्थान में अटल भू-जल योजना के लिए निम्न में से कौन सा/ से कथन सही है/हैं?
(i) अटल भूजल योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
(ii) इस योजना का फोकस भू-जल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है।
(1) न तो (i) न ही (ii) (2) केवल (ii) सही है।
(3) केवल (i) सही है। (4) (i) और (ii) दोनों सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-
- 1 अप्रैल, 2020 से अटल भू-जल योजना प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य भू-जल प्रबन्धन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। यह योजना राजस्थान के 17 जिलों में चलाई जा रही है।
- अटल भू-जल योजना का वित्त पोषण भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है।

24. राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन–सा तथ्य सही नहीं है?
(1) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
(2) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(3) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
(4) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-
- दिसम्बर, 2019 से राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गई। इस योजना में 10 करोड़ तक के ऋण पर 5%, रु. 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा रु. 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

25. वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा?
(1) परिवहन, भंडारण एवं संचार
(2) व्यापार, होटल एवं जलपान गृह
(3) स्थावर सम्पदा, आवासीय ग्रहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ
(4) वित्तीय सेवाएँ
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-
- वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 27.69 प्रतिशत रहा जो कि सर्वाधिक है जबकि इसमें सेवा क्षेत्र का कुल योगदान 43.74 प्रतिशत रहा।

26. गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA (स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर) में किसके योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है?
(1) इनमें से कोई नहीं (2) सेवा क्षेत्र
(3) उद्योग क्षेत्र (4) कृषि क्षेत्र
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-
- वर्ष 2022-23 में, राजस्थान में स्थिर मूल्य पर वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि होने का अनुमान है।
- सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जो GSVA का लगभग 2011-12 में 38.75 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 43.74 प्रतिशत है।

27. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II परियोजना के अंतर्गत 801 किमी. लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है?
(1) नाबार्ड
(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(3) विश्व बैंक
(4) एशियन विकास बैंक
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[3]**

व्याख्या:-
- भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौता किया है।
- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस परियोजना से राज्य के 801 किलोमीटर लंबे 11 राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा।

28. राजस्थान में किस एजेंसी को पी.एम. कुसुम योजना (कम्पोनेंट A) के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गयी है, जिसमें 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित किए जाने हैं?
(1) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशीयंसी
(2) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
(3) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
(4) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-
- 1 अप्रैल, 2023 से पी.एम. कुसुम योजना (कम्पोनेंट - A) किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत् राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कोटपूतली-बहरोड़ जिले के भालोजी में शुरू की गई। इस 0.5 से 2 MW संयंत्र हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी है।

29. राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
(1) 14 दिसम्बर (2) 5 जून
(3) 22 अप्रैल (4) 21 मार्च
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इस दिवस का आयोजन ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

30. राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया?
(1) 2008 (2) 2005
(3) 2003 (4) 2001
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-
- मई, 2005 में राजस्थान सरकार ने 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को अधिनियमित किया था। यह अधिनियम राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी, राजवित्तीय स्थिरता में संगत, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यमकालिक राजवित्तीय रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके राजवित्तीय प्रबंधन और राजवित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने का और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 को अगस्त 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

31. निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वस्थ एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है?
(1) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
(2) इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
(3) मिशन वात्सल्य योजना
(4) पालनहार योजना
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वस्थ एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 01 जनवरी, 2017 से मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू हो गया है। इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट शर्तों की पूर्ति पर परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे 5,000/- रुपये की नकद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

32. निम्नांकित में से कौन-सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है?
(1) महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना।
(2) मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन।
(3) महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
(4) बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार।
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[2]**

व्याख्या:-
- राज्य सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के तहत् राज्य की 11 से 45 वर्ष आयु की महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत् प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।

33. निम्नलिखित में से कौन-सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है?
(1) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
(2) महात्मा गाँधी जन भागीदारी विकास योजना
(3) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(4) संसद आदर्श ग्राम योजना
(5) अनुत्तरित प्रश्न **[1]**

व्याख्या:-
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) ग्रामीण समूहों को विकसित करने पर केंद्रित है।
- वर्ष 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल है।

2021

34. राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(1) इस योजना का नारा है 'आपणी योजना आपणो विकास है।
(2) इस योजना में वित्त पोषण के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है।
(3) इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है।
(4) पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्रिया गया है। **[1]**

व्याख्या:-
- चौदहवाँ वित्त आयोग के तहत् पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के विकास हेतु वर्ष 2015-16 से शत-प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को सीधे ही हस्तांतरित की जा रही है जिससे जमीनी स्तर पर नागरिकों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति हो सकें। इस हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य विशिष्ट मार्गदर्शिका "आपणी योजना आपणो विकास" तैयार की गई है। तथा इसे जयपुर में जिला/ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों तथा कार्मिको को वितरीत की गई है।

35. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है?
(1) 20 प्रतिशत (2) 40 प्रतिशत
(3) 30 प्रतिशत (4) 50 प्रतिशत **[2]**

व्याख्या:-
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा 40 प्रतिशत है तथा केन्द्र सरकार का हिस्सा 60 प्रतिशत है।
- इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक व कृषि विज्ञान की अच्छी आदतों का हस्तांतरण किया जा सके।

36. 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है –
(1) 52.19% (2) 14.32%
(3) 7.42% (4) 12.05% **[2]**

व्याख्या:-
- 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत 14.32 है।

37. राजस्थान में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है?
(1) मुख्यमंत्री कार्यालय

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(2) उद्योग निदेशालय
(3) आयोजना विभाग
(4) मानव संसाधन विकास विभाग **[3]**

व्याख्या:-

- राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है।

38. राजस्थान बजट 2021–22 के अनुसार, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी?

(1) जयपुर (2) सीकर
(3) जोधपुर (4) अजमेर **[3]**

व्याख्या:-

- राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में होगी। इस विश्वविद्यालय का नाम राजीव गाँधी के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

39. जनगणना – 2011 के अनुसार, भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमश: कितनी रही?

(1) 43.6% एवं 41.8%
(2) 39.8% एवं 43.6%
(3) 42.4% एवं 41.8%
(4) 39.8% एवं 36.4% **[2]**

व्याख्या:-

- जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमश: 39.8% तथा 43.6% रही।
- जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सहभागिता दर 41.8% जबकि शहरी क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर 35.31% रही है।
- जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर 47.3% जबकि शहरी क्षेत्रो में कार्य सहभागिता दर 32.27% रही।

40. अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में स्थिर कीमतों पर (2011-12) राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है–

(1) ₹ 79,722 (2) ₹ 97,227
(3) ₹ 72,297 (4) ₹ 75,527 **[3]**

व्याख्या:-

- अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2020-21 में स्थिर कीमतों पर (2011-12) राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय ₹ 72,297 है। गत वर्ष की तुलना में इसमें 7.77% का विचलन है।

41. आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है –

(1) ₹ 3.50 लाख (2) ₹ 4.00 लाख
(3) ₹ 4.50 लाख (4) ₹ 3.00 लाख **[3]**

व्याख्या:-

- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नाजुक या गंभीर बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि 4.50 लाख रुपये है तथा चिह्नित सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रुपये है।

2018
Rajastan Economy

42. वर्ष 2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक) में राजस्थान के कौन-से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल (Crude oil) का उत्पादन प्राप्त हुआ है?

(1) बीकानेर-नागौर बेसिन (2) जैसलमेर बेसिन
(3) बाड़मेर- सांचौर बेसिन (4) इनमें से कोई नहीं **[3]**

व्याख्या:–

- बाड़मेर-सांचौर बेसिन में वर्ष 2017-2018 (Dec. 2018 तक) में राजस्थान में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ है।

43. पचपदरा, बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) है?

(1) ONGC एवं भारत सरकार
(2) NTPC एवं राजस्थान सरकार
(3) HPCL एवं भारत सरकार
(4) HPCL एवं राजस्थान सरकार **[4]**

व्याख्या:-

- पचपदरा, बाड़मेर (राजस्थान) में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है।
- इसका शिलान्यास 1 जून, 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया।
- उपक्रम का नाम - HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
- साझेदारी HPCL : राजस्थान सरकार = 74: 26

44. राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है-

(1) 1999-2000 (2) 2005-2006
(3) 2010-2011 (4) 2011-2012 **[1]**

व्याख्या:-

- राजस्थान में सभी वस्तुओं के थोक मूल्य पर आधारित सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है 1

45. वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों (2011- 12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी-

(1) 7.16% (2) 6.23%
(3) 4.5% (4) 10.67% **[1]**

व्याख्या:-

- राजस्थान में स्थिर कीमतों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर–
  वर्ष 2017-18 - 7.16% वर्ष 2025-26 – 8.66%

46. हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन–सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रहा है?

(1) केन्द्रीय करों में हिस्सा (2) राज्य का कर राजस्व
(3) गैर-कर राजस्व (4) केन्द्रीय अनुदान **[2]**

व्याख्या:-

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

- राजस्थान के बजट (2020-21) में राज्य की सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति निम्न से रही–
  (1) राज्य का कर राजस्व (2) केन्द्रीय करों में हिस्सा
  (3) केन्द्रीय अनुदान (4) गैर कर राजस्व

47. निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है?
(1) सूरतगढ़ (2) छबड़ा
(3) कालीसिंध (4) कोटा **[1]**

व्याख्या:-

राजस्थान की प्रमुख तापीय परियाजनाएँ

1. कोटा सुपर पॉवर स्टेशन (KTPS), कोटा
- राज्य की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना जिसका प्रारम्भ वर्ष 1978 में किया गया।
- उत्पादन क्षमता – 1240 MW(2 x 100, 3 x 210, 2 x 195 MW)

2. सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन (श्रीगंगानगर)
- राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन है।
- उत्पादन क्षमता – 2820 MW
- सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पॉवर स्टेशन

3. छबडा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशन चौकी मोतीपुरा, छबड़ा (बाराँ)
- राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल तकनीक पॉवर प्लांट
- उत्पादन क्षमता – 2320 MW

4. गिरल लिग्नाइट थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट – थुम्बलि गिरल (बाडमेर)
- उत्पादन क्षमता 250 MW (2 x 125 MW)
- पहला गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी निगम लिमिटेड

5. कालीसिंध थर्मल पॉवर प्लांट (झालावाड़)
- उत्पादन क्षमता – 1200 MW (2 x 600 MW)

48. राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन-सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव (USP) नहीं है?
(1) पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन (शाही रेल)
(2) किले, महल एवं हवेलियाँ
(3) मेले एवं त्योहार
(4) चिकित्सकीय पर्यटन **[4]**

व्याख्या:-
- राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में अनुपम बिक्री प्रस्ताव (USP) में पैलेस ऑन व्हील्स (शाही रेल), रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, किले, हवेलियाँ, छतरियाँ, पैलेस, बावड़ियाँ, स्मारक, मेले व त्योहार, हैरिटेज होटल, एडवेंचर ट्यूरिज्म, ग्रामीण व इको ट्यूरिज्म, हस्तकला, लोकनृत्य व संगीत आदि प्रमुख है।

49. निम्न में से कौन–सा राजस्थान का तेल - क्षेत्र नहीं है?
(1) ऐश्वर्या (2) मंगला
(3) गंगा (4) सरस्वती **[3]**

व्याख्या:-
- राजस्थान के प्रमुख तेल क्षेत्र (कुएँ) निम्न है–

ऐश्वर्या	मंगला	भाग्यम
रागेश्वरी	शक्ति	सरस्वती
गुढ़ा	कामेश्वरी	

50. अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत माता-पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह निश्चित संयोग है-
(1) 1 लाख रुपये से कम - कम से कम 40%
(2) 1.5 लाख रुपये कम से कम - कम से कम 45%
(3) 2 लाख रुपये से कम - कम से कम 50%
(4) 2.5 लाख रुपये से कम - कम से कम 55% **[3]**

व्याख्या:-
- राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता-पिता की आय 2 लाख रुपये से कम तथा पूर्व परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों का निश्चित संयोजन रखा गया है जिसके तहत् स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल आदि कई शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस योजना में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु माता पिता की वार्षिक आय का दायरा 1 लाख से कम रखा गया है।

51. राजस्थान में स्वावलम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य है-
(1) निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना।
(2) बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
(3) अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार बालिकाओं को प्रशिक्षण देना।
(4) असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। **[1]**

व्याख्या:-
- वर्ष 2013 में प्रारम्भ राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन महिलाओं, विधवा महिलाओं, तलाकशुदा, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है।
- इस योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी की महिलाओं में कौशल विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके।

52. पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाये जाने वाला कार्यक्रम M(Power) किसके द्वारा समर्थित है?
(1) एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा
(2) जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (JICA) द्वारा
(3) कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा
(4) केनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (CIDA) द्वारा **[3]**

व्याख्या:-
- पश्चिमी राजस्थान में गरीबी निवारण की परियोजना (MPower) यह योजना सहयोग–
  (1) इंटरनेशनल फण्ड फोर एग्रीकल्चर डवलपमेंट (IFAD) द्वारा 124 करोड़ रु.
  (2) रतन टाटा ट्रस्ट 13 करोड़ रु.

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(3) राज्य सरकार अंशदान - 87.50 करोड़ रु.
(4) लाभ प्रदाताओं का योगदान- 10.50 करोड़ रु.
(5) बैंकों द्वारा ऋण - 56 करोड़ रु. प्रारम्भ में इसमें पश्चिमी राजस्थान के **6 ब्लॉकों–**
बाप (जोधपुर), साकडा (जैसलमेर), आबूरोड़ (सिरोही), सांचौर (जालोर), बाली (पाली) को शामिल किया गया था।

- वर्ष 2016-17 में दो अन्य ब्लॉक- बालेसर (जोधपुर), पिण्डवाडा (सिरोही) को जोड़ा गया।

53. राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है?
(1) परवन परियोजना (2) धौलपुर लिफ्ट परियोजना
(3) नर्मदा केनाल परियोजना (4) तकली परियोजना **[3]**

व्याख्या:-
- राजस्थान में नर्मदा केनाल (Canal) परियोजना के तहत् यह अनिवार्य हुआ कि कृषिगत सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति द्वारा ही की जायेगी।

2016

54. भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
(i) परिवार की सहमति से, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है।
(ii) भामाशाह नामांक का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है।
(1) केवल (i) सही है।
(2) केवल (ii) सही है।
(3) (i) एवं (ii) दोनों सही हैं।
(4) (i) एवं (ii) दोनों गलत हैं। **[1]**

व्याख्या:-
भामाशाह योजना के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्य
- प्रारंभ 2008 में
- पुनः प्रारम्भ - 15 अगस्त, 2014- उदयपुर से
- उद्देश्य- महिला सशक्तिकरण
- राजस्थान की प्रथम DBT योजना जिसमें परिवार की मुखिया महिला को बनाकर केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के लाभांश को सीधे महिला मुखिया के खाते में ट्रांसफर किये जाते है।

55. अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
(1) यह योजना अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
(2) यह योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है।
(3) यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
(4) यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यालयी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। **[*]**

व्याख्या:-
- इस प्रश्न को राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा निरस्त किया गया।

56. राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है–
(1) 1986-87 (2) 1999-2000
(3) 2004-05 (4) 2011-12 **[2]**

व्याख्या:-
- राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 = 100 है। थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है, जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

57. राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित हैं-
(1) 3.5%, 8.0% और 9.5%
(2) 4.0%, 8.0% और 9.0%
(3) 4.0%, 8.5% और 9.0%
(4) 3.5%, 8.5% और 9.5% **[1]**

व्याख्या:-
- राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः 3.5%, 8.0% और 9.5% निर्धारित हैं।

58. मुख्यमंत्री निः शुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी–
(1) 2 सितम्बर, 2011 (2) 2 सितम्बर, 2010
(3) 2 अक्टूबर, 2011 (4) 2 अक्टूबर, 2010 **[3]**

व्याख्या:-
- राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर, 2011 को लागू की गई।
- इस योजना के तहत् सभी मरीजों को सामान्य उपयोग के लिए दवाएँ सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

59. राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बी.पी.एल. अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा आई.आई.टी., आई.आई.एम. एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश होने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है-
(1) अनुप्रति योजना (2) छात्रवृत्ति स्कीम
(3) मैरिट कम मीन्स स्कीम (4) उच्च मैरिट छात्रवृत्ति **[1]**

व्याख्या:-
- राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना वर्ष 2005 से शुरू की गई।
- **पात्रता–** (1) परिवार की वार्षिक आय 2 लाख तक है।
  (2) अभ्यर्थी BPL परिवार से हो।
- **नोडल एजेंसी -** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

60. राजस्थान में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है-

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213

(1) राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लि.
(2) स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी
(3) सेन्टर फॉर न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी सौर्सेस
(4) इनमें से कोई नहीं **[1]**

व्याख्या:-

- राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास, संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी।
- स्थापना- 9 अगस्त, 2002 को पूर्व गठित REDA (1950) तथा RSPCL (1995) को मिलाकर की गयी।

61. राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है?

(1) 36 (2) 33
(3) 31 (4) 29 **[1]**

व्याख्या:-

- राजस्थान में जिला उद्योग केन्द्र- 36 उपकेन्द्र- 8
- **कार्य** –
  (1) हैण्डलूम तथा हैंडिक्राफ्ट उद्योग का विकास एवं संरक्षण।
  (2) लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना तथा उचित विपणन व्यवस्था मुहैया करवाना।

62. राजस्थान में कौन-सा मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है?

(1) बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना।
(2) बाल विवाह को रोकना।
(3) बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना।
(4) गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। **[4]**

व्याख्या:-

- राजस्थान में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गई।
- नोडल एजेंसी- परियोजना निदेशक परिवार कल्याण निदेशालय उद्देश्य –
  (1) बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना।
  (2) बाल विवाह रोकना।
  (3) महिला सशक्तिकरण

2015

63. वर्ष 2013-14 में राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था -

(1) मोटे अनाज (2) समस्त दालों
(3) रेपसीड (4) रेपसीड व सरसों **[4]**

व्याख्या:–

- वर्ष 2022-23 में राजस्थान का रेपसीड व सरसों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहा था। वर्तमान में राजस्थान सरसों, बाजरा, ईसबगोल, ग्वार, जीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।

64. नेशनल बाँस मिशन के अंतर्गत कौन-सा जिला शामिल नहीं है–

(1) जालोर (2) बाँसवाड़ा
(3) करौली (4) भीलवाड़ा **[1]**

व्याख्या:–

नेशनल बाँस मिशन- वर्ष 2006-07

- नेशनल बाँस मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 10 जिलों- सवाई माधोपुर, करौली, बाँसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़ और डूँगरपुर जिले आते हैं।
- वर्ष 2019 में बाँस को वृक्ष श्रेणी से हटाकर घास श्रेणी में प्रतिस्थापित कर दिया।

UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213